



e-ISSN:2582-7219



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 6, Issue 12, December 2023



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.54



6381 907 438



6381 907 438



ijmrset@gmail.com



www.ijmrset.com



राजस्थान के आर्थिक विकास में उद्योगों का योगदान: एक अध्ययन

DR. JUGAL KISHOR PAREEK

ASSISTANT PROFESSOR, DEPT. OF ABST, SRI BALDEV RAM MIRDHA GOVT. COLLEGE, NAGOUR, RAJASTHAN, INDIA

सार

• आजीविका यापन के लिए की जाने वाली सभी आर्थिक क्रियाएं जिसमें मुद्राओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिमय होता है, उद्योग कहलाता है।

राजस्थान में उद्योग के प्रकार-

(A) कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर-⁶

1. कृषि आधारित
2. खनिज आधारित
3. रसायन आधारित
4. अन्य उद्योग

○ राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग-

- वे उद्योग जिनमें कच्चा माल कृषि एवं कृषि संबंधी गतिविधियों से प्राप्त होता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाता है।
- राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग तीन क्षेत्रों – सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- सूती वस्त्र उद्योग
- चीनी उद्योग
- बायोडीजल उद्योग
- वनस्पति घी उद्योग
- मिल्क पाउडर उद्योग
- शराब उद्योग



○ सूती वस्त्र उद्योग-

परिचय

• सेठ दामोदर दास और कर्नल डिकसन द्वारा राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना वर्ष 1889 में ब्यावर (अजमेर) में 'दी कृष्णा मिल्स' के नाम से की गई। • सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन और परंपरागत संगठित उद्योग है। • इस उद्योग में रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध होता है। • वर्तमान में राज्य में सूती वस्त्र का उत्पादन मुख्यतः पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, श्रीगंगानगर, किशनगढ़ और बांसवाड़ा में किया जाता है।⁵

○ राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सूती वस्त्र कारखानों-

1. दी कृष्णा मिल्स – ब्यावर (अजमेर) – वर्ष 1889
2. दी एडवर्ड मिल्स – ब्यावर (अजमेर) – वर्ष 1906
3. श्री महालक्ष्मी मिल्स – ब्यावर (अजमेर) – वर्ष 1925
4. दी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स – भीलवाड़ा – वर्ष 1938
5. महाराजा उम्मेद मिल्स – पाली – वर्ष 1942
6. सार्दुल टेक्सटाइल मिल्स – श्रीगंगानगर – वर्ष 1946
7. जयपुर मिल्स - जयपुर - वर्ष 1935
8. बाँसवाड़ा मिल्स - बाँसवाड़ा - वर्ष 1944
9. श्री महावीर जूट मिल्स - जोधपुर - वर्ष 1948
10. बबूलल मिल्स - कोटा - वर्ष 1951

○ स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान में स्थापित सूती वस्त्र कारखानों (निजी क्षेत्र)-

1. श्री आदित्य कॉटन मिल्स – किशनगढ़ (अजमेर)
2. श्री विजय कॉटन मिल्स – विजयनगर (अजमेर)
3. राजस्थान सहकारी मिल्स – गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
4. उदयपुर टेक्सटाइल मिल्स – उदयपुर
5. राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स – भवानी मण्डी (झालावाड़)
6. श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल्स – कोटा⁴



○ राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में स्थापित सूती वस्त्र कारखाने-

1. राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) में स्थित है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी।
2. श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल्स हनुमानगढ़ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी।
3. गंगापुर सहकारी कताई मिल्स गंगापुर (भीलवाड़ा) में 1981 में स्थापित की गई थी।

• 1974 में वित्तीय रूग्णता के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने राजस्थान की तीन सूती वस्त्र मिल्स का अधिग्रहण कर सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया।

1. राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) में स्थित है जिसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई।
2. श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल्स हनुमानगढ़ में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई।
3. गंगापुर सहकारी कताई मिल्स गंगापुर (भीलवाड़ा) में वर्ष 1981 में स्थापित की गई।

• वित्तीय रूग्णता के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा सन् 1974 में राजस्थान की तीन सूती वस्त्र मिल्स का अधिग्रहण कर सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया-

1. दी एडवर्ड मिल्स
2. श्री महालक्ष्मी मिल्स
3. श्री विजय कॉटन मिल्स³

1 अप्रैल, 1993 को स्पिनफैड (SPINFED - राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एण्ड जिनिंग मिल्स संघ) की स्थापना की गई, जो राजस्थान में सहकारी तथा निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र कारखानों को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती है। SPINFED की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा सन् 1974 में राजस्थान की तीन सूती वस्त्र मिल्स का अधिग्रहण किया गया था, जिससे सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा मिला था।

1. राजस्थान सहकारी मिल्स – गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) (निजी क्षेत्र)
2. राजस्थान सहकारी कताई मिल्स – गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) (सहकारी क्षेत्र)
3. श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल्स – हनुमानगढ़ (सहकारी क्षेत्र)
4. गंगापुर सहकारी कताई मिल्स – गंगापुर (भीलवाड़ा) (सहकारी क्षेत्र)

• राजस्थान का मैनचेस्टर (वस्त्र नगरी) भीलवाड़ा को कहा जाता है।

विचार-विमर्श

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation popularly / RIICO) राजस्थान सरकार की प्रमुख एजेंसी है जिसने राजस्थान के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसकी स्थापना १९६९ में हुई थी। रीको निवेशकों/उद्यमियों को बड़ी, मंजोली और छोटी परियोजनाओं के लिए अनूठे सेवा पैकेज प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1996 में हो चुकी थी, लेकिन नवंबर, 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC) के अलग से स्थापित होने के बाद RIICO का कार्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया।²

राजस्थान मुख्यतः एक कृषि व पशुपालन प्रधान राज्य है और अनाज व सब्जियों का निर्यात करता है। अल्प व अनियमित वर्षा के बावजूद, यहाँ लगभग सभी प्रकार की फ़सलें उगाई जाती हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में बाजरा, कोटा में ज्वार व उदयपुर में मुख्यतः मक्का उगाई जाती हैं। राज्य में गेहूँ व जौ का विस्तार अच्छा-खासा (रेगिस्तानी क्षेत्रों को छोड़कर) है। ऐसा ही दलहन (मटर, सेम व मसूर जैसी खाद्य फलियाँ), गन्ना व तिलहन के साथ भी है। चावल की उन्नत किस्मों को भी यहाँ उगाया जाने लगा है। 'चंबल घाटी' और 'इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं' के क्षेत्रों में इस फ़सल के कुल क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। कपास व तंबाकू महत्वपूर्ण नक़दी फ़सलें हैं। हालाँकि यहाँ का अधिकांश क्षेत्र शुष्क या अर्द्ध शुष्क है, फिर भी राजस्थान में बड़ी संख्या में पालतू पशु हैं व राजस्थान सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला राज्य है। ऊँटों व शुष्क इलाकों के पशुओं की विभिन्न नस्लों पर राजस्थान का एकाधिकार है।

सिंचाई की व्यवस्था

अत्यधिक शुष्क भूमि के कारण राजस्थान को बड़े पैमाने पर सिंचाई की आवश्यकता है। जल की आपूर्ति पंजाब की नदियों, पश्चिमी यमुना (हरियाणा) और आगरा नहर (उत्तर प्रदेश) तथा दक्षिण में साबरमती व 'नर्मदा सागर परियोजना' से होती है। यहाँ हज़ारों की संख्या में जलाशय (ग्रामीण तालाब व झील) हैं, लेकिन वे सूखे व गाद से प्रभावित हैं। 'राजस्थान भांखड़ा परियोजना' में पंजाब और 'चंबल घाटी परियोजना' में मध्य प्रदेश का साझेदार राज्य है। दोनों परियोजनाओं से प्राप्त जल का उपयोग सिंचाई व पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता है। 1980 के दशक के मध्य में स्वर्गीय प्रधानमंत्री की स्मृति में 'राजस्थान नहर' का नाम बदलकर 'इंदिरा गांधी नहर' रखा गया, जो पंजाब की सतलुज और व्यास नदियों के पानी को लगभग 644 किलोमीटर की दूरी तक ले जाती है और पश्चिमोत्तर व पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि की सिंचाई करती है।

पशुधन

राजस्थान में पशु-सम्पदा का विशेष रूप से आर्थिक महत्त्व माना गया है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत मरुस्थलीय प्रदेश है, जहाँ जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन ही है। इससे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पात्ति का महत्त्वपूर्ण अंश प्राप्त होता है। राजस्थान में देश के पशुधन का लगभग 10.60 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें भेड़ों का 25 प्रतिशत अंश पाया जाता है। भारतीय संदर्भ में पशुधन के महत्त्व को दर्शाने के लिए नीचे कुछ आँकड़े दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं-

1. राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का अंश लगभग 12.73 प्रतिशत होता है।
2. राज्य के पशुओं द्वारा भार-वहन शक्ति 35 प्रतिशत है।
3. भेड़ के माँस में राजस्थान का भारत में अंश 30 प्रतिशत है।

4. ऊन में राजस्थान का भारत में अंश 40% है। राज्य में भेड़ों की संख्या समस्त भारत की संख्या का लगभग 25 प्रतिशत है।¹

महत्त्व

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में यह कहा जाता है कि यह पूर्णतः कृषि पर निर्भर करती है तथा कृषि मानसून का जुआ मानी जाती है। इस स्थिति में पशुपालन का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है। राजस्थान में पशुधन का महत्त्व निम्नलिखित तथ्यों से देखा जा सकता है-

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान - राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान लगभग 10%

प्रतिशत है।

निर्धनता उन्मूलन - निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में भी पशु-पालन की महत्ता स्वीकार की गई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गरीब परिवारों को दुधारु पशु देकर उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया गया था। लेकिन इसके लिए चारे व पानी की उचित व्यवस्था करनी होती है तथा लाभान्वित परिवारों को बिक्री की सुविधाएं भी प्रदान करनी होती हैं।

रोज़गार-सृजन - पशुपालन में ऊँची आमदनी व रोज़गार की संभावनाएँ निहित हैं। पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाकर आमदनी में वृद्धि की जा सकती है। राज्य के शुष्क व अर्द्ध-शुष्क भागों में कुछ परिवार काफ़ी संख्या में पशुपालन करते हैं और इनका यह कार्य वंश-परम्परागत चलता आया है। इन क्षेत्रों में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का ऊँचा अंश पशुपालन से सृजित होता है। इसलिए मरु अर्थव्यवस्था मूलतः पशु-आधारित है।

डेयरी विकास - पशुधन की सहायता से ग्रामीण दुग्ध उत्पादन को शहरी उपभोक्ताओं के साथ जोड़कर शहरी क्षेत्र की दुग्ध आवश्यकता की आपूर्ति तथा ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका की व्यवस्था होती है। राजस्थान देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 10 प्रतिशत उत्पादन करता है। राज्य में 1989-1990 में 42 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ, जो बढ़कर 2003-2004 में 80.5 लाख टन हो गया। परिवहन का साधन - राजस्थान में पशुधन में भार वहन करने की अपार क्षमता है। बैल, भैंसे, ऊँट, गधे, खच्चर आदि कृषि व कई परियोजनाओं में बोझा ढोने व भार खींचने का काम करते हैं। देश की कुल भार वहन क्षमता का 35 प्रतिशत भाग राजस्थान के पशु वहन करते हैं। देश में रेल व ट्रकों द्वारा कुल 30 करोड़ टन माल की ढुलाई होती है, जबकि बैलगाडियों से आज भी 70 करोड़ टन माल ढोया जाता है।

खाद की प्राप्ति - पशुपालन के द्वारा कृषि के लिए खाद की प्राप्ति भी होती है। इस समय जानवरों के गोबर से निर्मित "वर्मी कम्पोस्ट" खाद्य अत्यधिक प्रचलन में है।²

पशुधन की संरचना

राजस्थान राज्य में विभिन्न प्रकार के पशु पाए जाते हैं, जिनकी संख्या को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है-

2019 में विभिन्न प्रकार के पशुओं की संख्या-

- गौवंश अथवा गाय-बैल - 1.33 करोड़
- भैंस जाति - 1.29 करोड़

- भेड़ जाति - 90.79 लाख
- बकरी जाति - 2.16 करोड़
- शेष ऊँट, घोड़े, गधे, सूअर आदि - 10 लाख

इस प्रकार संख्या की दृष्टि से पशुओं में गाय-बैल तथा भेड़-बकरी प्रमुख हैं। राजस्थान में उपलब्ध विभिन्न जानवरों, जैसे- गाय, बकरी, भेड़ आदि का वर्णन निम्नलिखित है-

(1.) गाय - राजस्थान में गाय पशुपालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कुल पशु-सम्पदा में गौवंश का 24.4 प्रतिशत है। इसकी निम्नलिखित नस्लें राजस्थान में पाई जाती हैं-³

1. नागौरी
2. कांकरेज
3. थारपारकर
4. राठी

(2.) भेड़ - देश की कुल भेड़ों की लगभग 10.64

प्रतिशत राजस्थान में पाई जाती हैं। राज्य के लगभग 2 लाख परिवार पशुपालन कार्यों में संलग्न हैं। यहाँ पाई जाने वाली भेड़ों की प्रमुख नस्लें इस प्रकार हैं-

1. जैसलमेरी भेड़
2. नाली भेड़
3. मालपुरी भेड़
4. मगरा भेड़
5. पूगल भेड़
6. मारवाड़ी भेड़
7. शेखावाटी भेड़ या चोकला
8. सोनाडी भेड़

पशुधन विकास की समस्याएँ

मानसून की अनिश्चिता - राजस्थान में प्रायः सूखे की समस्या रहती है। इसी वजह से पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। योजना एवं समन्वय का अभाव- सरकार अभी तक इस क्षेत्र के विकास के लिए एक सम्पूर्ण योजना का खाका तैयार नहीं कर पायी है, तथा समन्वय का अभाव देखा गया है। पशु स्वास्थ्य योजना - अक्सर देखा जाता है कि किसी एक बीमारी के कारण सभी पशु उसकी चपेट में आ जाते हैं। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए योजना एवं सुविधाओं का अभाव देखा गया है। पशु आधारित उद्योगों की कमी - राजस्थान में ऊन, दूध तथा चमड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परन्तु इन पर आधारित उद्योगों की राजस्थान में

कमी होने से दूध, चमड़ा दूसरे राज्यों में निर्यात कर देने से राज्य को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है।⁴

विकास हेतु समाधान

राजस्थान में पशुधन का बेहतर प्रयोग हो सके और इससे अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके, इसके लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

गोपाल कार्यक्रम

पशुधन के विकास हेतु यह कार्यक्रम 1990-1991 में चालू किया गया था। इस गैर-सरकारी संगठन अथवा गांव के शिक्षित युवक (गोपाल) को उचित प्रशिक्षण देकर उसकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें विदेशी नस्ल का उपयोग बढ़ाने के लिए गोपाल को क्रॉस प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधान की विधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक क्षेत्र के बेकार साड़ों को पूर्णतः बधिया दिया जाता है। पशुपालकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे अपने पशुओं को स्टॉल पर किस प्रकार खिलावें और सदैव बाहर चरने की विधि पर आश्रित न हों।⁵

भेड़ प्रजनन कार्यक्रम

राज्य में ऊन व मांस के उत्पादन में गुणात्मक व मात्रात्मक सुधार करने के लिए भेड़ प्रजनन कार्य में सुधार के व्यापक प्रयास किए गए हैं। क्रॉस-प्रजनन कार्यक्रम मारवाड़ी, जैसलमेरी, एवं मगरा भेड़ नस्लों पर लागू किया गया है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भेड़ों की नस्ल सुधारी जाती है। इसके अलावा चयनित प्रजनन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

विपणन व्यवस्था

पशुपालकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए एक तरफ पशुओं के क्रय-विक्रय हेतु पशु मेला लगाये जाते हैं। दूसरी तरफ दूध को बिना मध्यस्थों के सीधा उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना की गयी है। राज्य में पशु मेलों का आयोजन ग्राम पंचायत, नगरपालिका एवं पंचायत समितियों के माध्यम से किये जाता है। राज्य में वर्तमान में 50 पशु मेले लगते हैं, जिनमें 10 मेले राज्य स्तरीय प्रसिद्ध पशु मेले, पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किये जाते हैं।

पशु चिकित्सा

राज्य में पशुओं की बीमारियों से रक्षा एवं रोकथाम के लिये नये चिकित्सालय खोले गये हैं, जहाँ 1951 में 147 चिकित्सालय थे। 2001-2002 में राज्य में 12 पशु क्लिनिक्स, 22 प्रथम ग्रेड के पशु चिकित्सालय, 1386 पशु चिकित्सालय, 285 पशु औषधालय तथा 1720 उपकेन्द्र कार्यरत हैं। इसके अलावा 34 ज़िला रोग प्रयोगशालाएँ राज्य में कार्यरत हैं। पशुपालकों को उनके घर पर ही पशु चिकित्सा



सेवा उपलब्ध कराने हेतु उपखण्ड स्तर पर 8 चल पशु चिकित्सा इकाइयाँ गठित करने की योजना बनाई है।⁶

एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम

8वीं योजना के प्रारम्भ में यह जयपुर एवं बीकानेर संभाग में चालू किया गया था, परन्तु वर्तमान में यह कार्यक्रम प्रदेश के कोटा, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर संभागों के 21 जिलों में लागू हैं, जहाँ 749 उपकेन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस योजना में पशुओं के स्वास्थ्य के अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान, बेकार पशुओं का बन्ध्याकरण तथा उन्नत किस्म के चारे के बीजों का वितरण का उद्देश्य शामिल है।

पशुपालन व अनुसंधान

राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दो पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर तथा जयपुर में स्थापित किये गये हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीकानेर एवं सूरतगढ़ में भेड़ अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये हैं। जोधपुर में ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया है। विश्व बैंक की सहायता से जामडोली में पशु चिकित्सकों एवं अधिकारियों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण हेतु राजस्थान पशु-धन प्रबंध संस्थान का भवन निर्माण कार्य करवाया है।⁷

परिणाम

भारत के सांद्रित जस्ता, सीसा, पन्ना व गार्नेट का संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में ही होता है। प्रदेश जिप्सम व चांदी अयस्क उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत भाग भी राजस्थान में होता है। यहाँ के प्रमुख उद्योग वस्त्र, वनस्पति तेल, ऊन, खनिज, व रसायन पर आधारित हैं, जबकि चमड़े का सामान, संगमरमर की कारीगरी, आभूषण निर्माण, मिट्टी के बर्तन का निर्माण और पीतल का जड़ाऊ काम इत्यादि जैसे हस्तशिल्पों से काफ़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अनेक औद्योगिक राजधानी कोटा में नायलॉन और सूक्ष्म उपकरण बनाने की फ़ैक्ट्री के साथ-साथ कैल्शियम कार्बाइड, कास्टिक सोडा व रेयॉन टायर के तार निर्माण के संयंत्र भी हैं। उदयपुर में ज़िंक गलाने का संयंत्र है। राज्य को विद्युत आपूर्ति पड़ोसी राज्यों व चंबल घाटी परियोजना से होती है। कोटा के निकट रावतभाटा में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है।

पचपदरा रिफ़ाइनरी तेल शोधनागार भारत के राजस्थान के बालोतरा जिले में एक आगामी सार्वजनिक क्षेत्र की रिफ़ाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर है। यह रिफ़ाइनरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है और इसका अनुमानित लागत ₹1.4 ट्रिलियन है।^[1]

स्थिति

पचपदरा रिफ़ाइनरी राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा तहसील में स्थित है। यह तहसील बालोतरा शहर से लगभग 10 किलोमीटर में स्थित है।⁹

परियोजना



पचपदरा रिफाइनरी एक कच्चे तेल की रिफाइनरी होगी जो प्रतिदिन 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल को परिष्कृत करेगी। यह रिफाइनरी पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन, एलपीजी, और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करेगी।

इस रिफाइनरी का निर्माण हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। रिफाइनरी के लिए भूमि अधिग्रहण 2015 में शुरू हुआ और निर्माण 2017 में शुरू हुआ।^[2]

लाभ

पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।^[3] यह रिफाइनरी हजारों लोगों को रोजगार देगी और राजस्थान के निर्यात में वृद्धि करेगी।

रिफाइनरी राजस्थान के ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। यह रिफाइनरी राजस्थान को अपने स्वयं के कच्चे तेल को परिष्कृत करने की अनुमति देगी, जिससे राज्य को आयात पर निर्भरता कम होगी।^[4]

निष्कर्ष

विवाद

पचपदरा रिफाइनरी के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर कुछ विवाद हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण गलत तरीके से किया गया है और इससे स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ है।

इसके अलावा, कुछ लोगों का कहना है कि रिफाइनरी पर्यावरण के लिए हानिकारक होगी। वे चिंतित हैं कि रिफाइनरी से वायु और जल प्रदूषण होगा।^[5]

भविष्य

पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह रिफाइनरी राजस्थान के आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगी।

रिफाइनरी के पूरा होने पर, यह राजस्थान को एक प्रमुख तेल और गैस उत्पादन केंद्र में बदल देगी।¹⁰

संदर्भ

1. "Sectoral Portal". industries.rajasthan.gov.in. अभिगमन तिथि 2023-02-28.
2. "जनसंख्या अनुमान 2019" (पीडीएफ) ।
3. ^ "जनगणना 2011" (पीडीएफ) ।
4. ^ "राजस्थान बजट विश्लेषण 2022-23"। पीआरएस विधायी अनुसंधान। 12 मार्च 2022को लिया गया।
5. ^ "एसडीजी इंडिया इंडेक्स" । नीति आयोग . 31 दिसंबर 2019.



6. ^ "भारत में बेरोजगारी दर" । भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र। पी। 1 . 3 नवंबर 2020 को लिया गया .
7. ^ "राजस्थान की अर्थव्यवस्था" । Mapsofindia.com । 7 अगस्त 2016 को लिया गया ।
8. ^ "गेहूं उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर - टाइम्स ऑफ इंडिया" । टाइम्सऑफइंडिया.इंडियाटाइम्स.कॉम। 20 मार्च 2016 । 7 अगस्त 2016 को लिया गया ।
9. ^ "राजस्थान की अर्थव्यवस्था का व्यापक अवलोकन" । बस विकी। 11 जुलाई 2016. 18 अगस्त 2016 को मूल से संग्रहीत । 7 अगस्त 2016 को लिया गया ।
10. ^ "राजस्थान अर्थव्यवस्था" । Business.mapsofindia.com । 10 जनवरी 2017 को लिया गया .



INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor
7.54

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com